



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 28, 2019/आश्विन 6, 1941

No. 571]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 28, 2019/ASVINA 6, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2019

सं. 39/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 696(अ).—जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित और भारत में आयातित "डकटाइल आयरन पाइप्स" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7303 00 30 या 7303 00 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में अधिसूचना संख्या 15/1006/2012-डीजीएडी, दिनांक 04 सितम्बर, 2013, जिसे दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी;

और जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस विषयगत माल पर दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 से प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहाँ कि मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड के द्वारा दायर स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 12368/2018 के मामले में आए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 09 अक्टूबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1012 (अ), दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क को 09 अप्रैल, 2019 तक बढ़ा दिया था;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "डक्टाइल आयरन पाइप्स" के आयात के बारे में अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 7/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 के तहत सनसैट रिव्यू जांच शुरू की थी;

और जहां कि उक्त सनसैट रिव्यू जांच के पूरा हो जाने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "डक्टाइल आयरन पाइप्स" के आयात के बारे में अधिसूचना संख्या 7/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों को जारी किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने उक्त निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की जरूरत नहीं है और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "डक्टाइल आयरन पाइप्स" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को और आगे जारी रखने की सिफारिश नहीं की थी;

और जहाँ मैसर्स जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 6896/2019 के मामले में दिनांक 05 अप्रैल, 2019 को आए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 18/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 299(अ) दिनांक 10 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा 09 मई, 2019 तक के लिए बढ़ा दिया था;

और जहाँ कि मैसर्स जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 6896/2019 के मामले में आए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 03 मई, 2019 के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने विषयगत वस्तु पर लगने वाले शुल्क को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 09 मई, 2019, जिसे सा.का.नि. 352 (अ.), दिनांक 09 मई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा 23 जून, 2019 तक बढ़ा दिया है;

और जहां कि मैसर्स जिंदल साँ लिमिटेड के द्वारा दायर स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नं. 6896/2019 के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 20 जून, 2019 के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व सरकार) की अधिसूचना संख्या 25/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जून, 2019, जिसे सा.का.नि. 444 (अ), दिनांक 23 जून, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3 उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त विषयगत वस्तु पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क को 9 अक्टूबर, 2019 तक बढ़ा दिया था;

और जहां कि व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा दायर सिविल अपील संख्या 6678/2019 (स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नं. 6896/2019 के मामले में 20 जून, 2019 के निर्णय से उत्पन्न) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 28 अगस्त 2019 के आदेश द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 20 जून, 2019 के निर्णय को निरस्त करने का आदेश दिया है।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013, सीमा शुल्क, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई या करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 354/3/2007-टीआरयू (पार्ट. I)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2019

No. 39/2019-Customs (ADD)

G.S.R. 696(E).—Whereas in the matter of ‘Ductile iron pipes’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 7303 00 30 or 7303 00 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification number 15/1006/2012-DGAD, dated the 4th September, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 4th September, 2013, had recommended continuation of anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on the subject goods with effect from the 10th October, 2013 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 23/2013-Customs (ADD), dated the 10th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 680 (E), dated the 10th October, 2013;

And whereas, in pursuance of the Judgement dated the 26th September, 2018 of Hon’ble High Court of Gujarat in the matter of Special Civil Application No. 12368 of 2018, filed by M/s Jindal Saw Limited, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods upto the 9th April, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/2018-Customs (ADD), dated the 9th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1012 (E), dated the 9th October, 2018;

And whereas, the designated authority had initiated the review investigation *vide* notification No. 7/18/2018-DGAD, dated the 9th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 9th October, 2018, concerning imports of subject goods originating in or exported from China PR;

And whereas, on completion of review investigation, the designated authority issued final finding *vide* notification No. 7/18/2018-DGAD, dated the 1st April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st April, 2019 concerning imports of subject goods originating in or exported from China PR and the designated authority *vide* the said findings concluded that continuation of anti-dumping duty was not warranted and did not recommend further extension of anti-dumping duty on import of subject goods originating in or exported from China PR;

And whereas, in pursuance of the Judgement dated the 5th April, 2019 of Hon’ble High Court of Gujarat in the matter of Special Civil Application No. 6896 of 2019, filed by M/s Jindal Saw Limited, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods upto the 9th May, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 18/2019-Customs (ADD), dated the 10th April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 299 (E), dated the 10th April, 2019;

And whereas, in pursuance of the Judgement dated the 3rd May, 2019 of Hon’ble High Court of Gujarat in the matter of Special Civil Application No. 6896 of 2019, filed by M/s Jindal Saw Limited, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods upto the 23rd June, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2019-Customs (ADD), dated the 9th May, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 352 (E), dated the 9th May, 2019;

And whereas, in pursuance of the Judgement dated the 20th June, 2019 of Hon’ble High Court of Gujarat in the matter of Special Civil Application No. 6896 of 2019, filed by M/s Jindal Saw Limited, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods upto the 9th October, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 25/2019-

Customs (ADD), dated the 23rd June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 444 (E), dated the 23rd June, 2019;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in the matter of Civil Appeal No. 6678 of 2019 (arising out of order dated 20.06.2019 in SCA No 6896/2019), filed by Directorate General of Trade Remedies, *vide* order dated the 28th August 2019, has set aside the said order dated 20.06.2019 of High Court of Gujarat.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping-duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 23/2013-Customs(ADD), dated the 10th October 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 680 (E), dated the 10th October 2013, except as respects things done or omitted to be done before such recession.

[F. No. 354/3/2007-TRU (Pt-I)]

RUCHI BISHT, Under Secy.